डिजिटल रुपी का इस्तेमाल पारंपरिक रुपये के साथ होता रहेगा, यह सिक्के या पारंपरिक नोट जैसी ही है, फर्क इतना है कि अस्तित्व डिजिटल होगा...

# डिजिटल रुपी बदल देगा देश में लेनदेन का पारंपरिक तरीका

## एक अप्रैल, 2022 से शुरू नए वित्त वर्ष में आरबीआई लाएगा अपनी डिजिटल करेंसी

फर्क सीएनवाई परियोजना से चीन ने 2020 में युआन का डिजिटल करेंसी परीक्षण शुरू किया। वहां के प्रमुख शहरों में लोगों को 200 डिजिटल युआन मुफ्त दिया गया है, जिन्हें 14 दिन में खर्च करने को कहा गया। दुकानदारों को इसे करेंसी नोट जैसा ही मानने को कहा गया। परीक्षण सफल रहा। आज इस डिजिटल युआन को रेनमिनबी नाम से सभी एप स्वीकार कर रहे हैं। बीजिंग ओलंपिक में चीन इसे दुनिया के सामने रख सकता है।

ऐसी ही पहल भारत में भी इस साल होने जा रही है। आम बजट में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) शुरू करने की घोषणा इसकी शुरुआत है। इससे न सिर्फ पारंपरिक लेनदेन का तरीका बदल जाएगा बल्कि उद्योगों में पारदर्शिता भी आएगी। आरबीआई के कंधे पर इसे नए वित्त वर्ष से शुरू करने की जिम्मेदारी है। पारंपरिक रुपये के साथ इसका इस्तेमाल होता रहेगा। यह करेंसी किसी पारंपरिक नोट या सिक्के जैसी ही है। फर्क इतना है कि अस्तित्व डिजिटल या वर्चुअल है। आरबीआई इसे जारी करेगा, इसलिए इसकी विश्वसनीयता वैसी ही रहेगी।

- **खतरे भी कायम :** डिजिटल करेंसी में सबसे बड़ा खतरा डिजिटल धोखाधड़ी या साइबर अपराध का है। इसे एक पुख्ता व्यवस्था से ही सुरक्षित रखा जा सकता है। साइबर ठगों से बचाने के लिए नागरिकों को इसके उपयोग को लेकर जागरूक करना भी एक चुनौती होगी।

**86%**

केंद्रीय बैंक विभिन्न देशों में डिजिटल करेंसी लाने पर कर रहे विचार

### किसे क्या फायदा

- **सरकार :** आज फिजिकल नोट छापना, चलाना, संभालना सरकार के लिए चुनौती है। सीबीडीसी इन समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। इसके साथ ही कालेधन और भ्रष्टाचार पर लगाम कसेगी।
- **आम लोग :** नकदी की सुरक्षा की चिंता से छुटकारा मिलेगा। जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं, वे भी बैंकिंग प्रणाली में शामिल हो सकेंगे। एप और फिनटेक कंपनियां अपने मंच से लेनदेन के लिए ग्राहकों को ऑफर भी दे सकती हैं।
- **देश :** 90 फीसदी अंतरराष्ट्रीय कारोबार अमेरिकी डॉलर में होता है। भारत के लिए सही समय है कि डिजिटल रुपये को मजबूती और विश्वसनीयता से वैश्विक मंच पर पेश करे।

### भारत-चीन ही नहीं, पूरी दुनिया में परीक्षण

**14%**

देशों में इन्हें पायलट प्रोजेक्ट या अन्य किसी रूप में नागरिकों को दिया गया है

**60%** देश डिजिटल करेंसी का परीक्षण ढांचा बना रहे हैं

*स्वीडन ने डिजिटल क्रोना का परीक्षण शुरू किया है तो बहामास ने डिजिटल सैंड डॉलर नागरिकों को दिया है।*

### डिजिटल और क्रिप्टोकरेंसी में फर्क

#### डिजिटल करेंसी...

केंद्रीकृत व्यवस्था के नियंत्रण में रहती है। यानी सरकार या आरबीआई इसे नियंत्रित करते हैं।

इसके लिए कानूनी ढांचा भी बनाया जाता है।

लेनदेन गुप्त रहता है। एक व्यक्ति ने दूसरे को कब और कितने रुपये दिए, यह जानकारी सार्वजनिक मंच पर दिखाने की जरूरत नहीं होती। हालांकि, सरकार नजर रखती है।

#### क्रिप्टोकरेंसी...

विकेंद्रीकृत व्यवस्था में चलती है। किसी देश, सरकार या बैंक का नियंत्रण नहीं होता है।

किसी कानूनी ढांचे के अधीन नहीं आती।

यहां लेनदेन का लेखाजोखा वर्चुअल मंच पर सार्वजनिक रहता है। बिटकॉइन की तरह इसे कोई भी देख सकता है। क्रिप्टोकरेंसी पूरी तरह एनक्रिप्टेड होती है।

#### कम होगा मकान खरीदारों का पैसा डूबने का जोखिम

डेवलपर्स एसोसिएशन नरेडको ने कहा कि डिजिटल करेंसी की मदद से उद्योग का कामकाज आसान होगा। इससे न सिर्फ पैसा डूबने का जोखिम कम हो जाएगा बल्कि ग्राहकों में भरोसा बढ़ेगा।